

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2260
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

पोषण 2.0

2260. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सितंबर 2025 तक पोषण 2.0 के अंतर्गत आदिवासी महिलाओं और बच्चों में पोषण संबंधी परिणामों का जिला-वार आंकड़ा संकलित किया है;
- (ख) यदि हाँ, तो आदिवासी जनसंख्या में राष्ट्रीय औसत से अधिक एनीमिया और कुपोषण के प्रसार की दर का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इन संकेतकों को सुधारने में आदिवासी स्वास्थ्य/वेलनेस केंद्रों और पोषण वाटिकाओं के प्रभाव का आकलन किया है: और
- (घ) यदि हाँ, तो इसके प्रमुख निष्कर्षों सहित इस प्रकार के आकलन रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

(क) और (ख): 'पोषण ट्रैकर' ऐप को दिनांक 1 मार्च 2021 को एक महत्वपूर्ण संचालन उपकरण के रूप में शुरू किया गया था। पोषण ट्रैकर सभी आँगनवाड़ी केन्द्रों, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा लाभार्थियों की पारिभाषिक संकेतकों पर निगरानी एवं ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। पोषण ट्रैकर के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का उपयोग बच्चों में बौनापन, दुबलापन तथा कम वज़न की व्यापकता की सटीक पहचान हेतु किया जा रहा है। कुपोषण सूचकों का राज्यवार जिला-वार और जनजातीय जिलों सहित कुपोषण संकेतकों का विस्तृत विवरण <https://www.poshantracker.in/statistics> पर उपलब्ध है।

एनएफएचएस-5 (2019-2020) के अनुसार, भारत की जनजातीय आबादी में 15-49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता से संबंधित विवरण **अनुलग्नक-1** में दिए गए हैं।

(ग) और (घ): मिशन पोषण 2.0 का एक प्रमुख घटक यह है कि पोषण वाटिकाओं अथवा पोषण-उद्यानों के माध्यम से उपयुक्त पोषण उपलब्ध कराया जाए। इन्हें देशभर में स्थापित किया जा रहा है ताकि फल, सब्जियाँ, औषधीय पौधे तथा जड़ी-बूटियाँ आसानी से और कम दाम में उपलब्ध हो सकें। आहार-विविधता तथा स्थानीय, पौष्टिक उत्पादों के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए आँगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिकाएँ बनाई गई हैं।

पोषण वाटिकाएँ वर्षभर विविध फल, मेवे, जड़ी-बूटियाँ, औषधीय पौधे तथा सब्जियाँ उपलब्ध कराकर आहार-विविधता की उस महत्वपूर्ण कमी को पूरा करने में सहायता करती हैं, जिसका उल्लेख विभिन्न सर्वेक्षणों में बार-बार किया गया है। पोषण वाटिका की अवधारणा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य समुदाय के सदस्यों को अपने घरों के आँगन में स्थानीय खाद्य फसलों की खेती हेतु प्रोत्साहित करना है। पोषण उद्यान ताज़े फल और सब्जियों की सस्ती, नियमित तथा सुविधाजनक उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जो उत्तम पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। हरी सब्जियाँ और मौसमी फल विटामिन तथा खनिजों से भरपूर होते हैं, जो सूक्ष्म-पोषक तत्वों की कमी तथा रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

वर्ष 2021 में विश्व बैंक ने 11 प्राथमिकता वाले राज्यों जैसे-आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश—में पोषण सेवाओं की आपूर्ति का मूल्यांकन करने हेतु एक सर्वेक्षण आयोजित किया। निष्कर्षों से यह प्रदर्शित हुआ कि पोषण अभियान के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, - अर्थात् आवश्यक संदेशों की प्राप्ति, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा गए घर-घर जाना, तथा समुदाय आधारित कार्यक्रमों में सहभागिता-बेहतर पोषण संबंधी व्यवहारों से संबंधित थीं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि कार्यक्रम के पोषण संदेश 80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं तक पहुँचे और 81 प्रतिशत महिलाओं ने पहले छह महीनों तक केवल स्तनपान करवाया।

वर्ष 2020 में नीति आयोग द्वारा पोषण अभियान का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन एवं प्रभावी आकलन किया गया तथा सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए यह मूल्यांकन वर्ष 2025 में किया गया। इन मूल्यांकनों में पाया गया कि देश में कुपोषण से निपटने के लिए इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता संतोषजनक है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्व में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और अरोग्य केंद्र) स्वास्थ्य सेवाओं में चयनात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़कर एक व्यापक सेवा-पैकेज प्रदान करने का प्रयास है, जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, पुनर्वास एवं उपशामक देखभाल शामिल हैं। इसके दो परस्पर पूरक घटक हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की परिकल्पना इस प्रकार की गई है कि वे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से आगे बढ़कर विस्तृत सेवाएँ प्रदान करें, जिनमें गैर-संचारी रोगों की देखभाल, उपशामक एवं पुनर्वास सेवाएँ, मुख, नेत्र एवं ईएनटी सेवाएँ, मानसिक स्वास्थ्य, आपातकालीन एवं आघात की प्राथमिक देखभाल, तथा निःशुल्क आवश्यक दवाएँ और नैदानिक सेवाएँ शामिल हों।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एएएम पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31.10.2025 तक भारत में कुल 1,80,906 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्व में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं अरोग्य केंद्र) उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ कर संचालित किए गए हैं।

विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय, नीति आयोग ने जुलाई 2024 में एएएम कार्यक्रम का मूल्यांकन किया है जिसका उद्देश्य इसके कार्यान्वयन तथा प्रभाव का आकलन करना है। इस अध्ययन में कई उत्साहजनक निष्कर्ष सामने आए हैं जिनमें स्वास्थ्य अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार तथा समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत उपलब्धता के कारण इनमें आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इनमें विशेष रूप से एनसीडी प्रबंधन, सामान्य ओपीडी सेवाएँ, निःशुल्क औषधियाँ और डायग्नोस्टिक्स जैसी सुविधाओं तक बेहतर पहुँच शामिल है। समुदाय स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति से प्रमुख सेवाओं की प्रदायगी बढ़ी है जबकि ई-संजीवनी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच को बढ़ाया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। यह समीक्षा बैठकों, प्रमुख लक्ष्यों की मध्यावधि समीक्षा, वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्रीय निरीक्षण, सेवा प्रदायगी के लिए मानक स्थापित कर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने तथा उत्कृष्ट उपलब्धियों को पुरस्कृत करने जैसे उपायों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत प्रगति एवं कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन एवं निगरानी करने के लिए साझा समीक्षा मिशन (कॉमन रिव्यू मिशन) भी प्रतिवर्ष संचालित किए जाते हैं।

अनुलग्नक I

“पोषण 2.0” के संबंध में डॉ. डी रवि कुमार द्वारा पूछे गए दिनांक 12.12.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न संख्या 2260 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एनएफएचएस-5 (2019-2020) के अनुसार भारत की जनजातीय आबादी में महिलाओं (15-49 वर्ष) में एनीमिया के व्याप्तता का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिलाओं में एनीमिया (15-49 वर्ष)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30.5
2	आंध्र प्रदेश	62.6
3	अरुणाचल प्रदेश	36.3
4	असम	69.2
5	बिहार	64.7
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ़	70.9
8	दादरा और नगर हवेली	70.9
9	दिल्ली	51.5
10	गोवा	42.5
11	गुजरात	78.3
12	हरियाणा	64.2
13	हिमाचल प्रदेश	53.8
14	जम्मू और कश्मीर	68.6
15	झारखंड	72
16	कर्नाटक	46.2
17	केरल	52.9
18	लद्दाख	92.4
19	लक्षद्वीप	24.2
20	मध्य प्रदेश	64.2
21	महाराष्ट्र	59.7
22	मणिपुर	26.8
23	मेघालय	53.3
24	मिजोरम	34.3
25	नागालैंड	27.7
26	ओडिशा	71.7

27	पुदुच्चेरी	67.3
28	पंजाब	54.4
29	राजस्थान	61.6
30	सिक्किम	42.6
31	तमिलनाडु	59
32	तेलंगाना	64
33	त्रिपुरा	66.8
34	उत्तर प्रदेश	51.1
35	उत्तराखंड	56
36	पश्चिम बंगाल	82.4

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
